दैनिक जागरण
व्यवहार व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होता है

फैसले की घड़ी

अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने जिस तरह यह स्पष्ट किया कि 18 अक्टूबर के बाद सभी पक्षकारों को जिरह के लिए एक दिन भी अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा उससे यही प्रकट होता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के इस मसले पर अपना फैसला देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के साथ ही उसने यह भी रेखांकित किया कि 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी होने पर ही चार सप्ताह में फैसला देने की उम्मीद की जा सकती है। चार सप्ताह का जिक्र इसीलिए हुआ, क्योंकि इस संविधान पीठ में शामिल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। यदि किन्हीं कारणों से उनकी सेवानिवृत्ति के पहले अयोध्या मसले पर फैसला नहीं आ पाता तो फिर मामले की सुनवाई नए सिरे से करनी होगी। यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो यह गहन निराशा का कारण बनेगा। इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की उम्मीद जगा दी है। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए साधुवाद कि उसने इस मामले की अहमियत को समझा और फैसला करने की ठानी। अयोध्या मामले की नियमित सुनवाई के पहले उसने आपसी बातचीत के जरिये इस विवाद को सुलझाने की पहल की, लेकिन वह नाकाम रही। हालांकि मध्यस्थता की पहल नए सिरे से शुरू हुई है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि वह किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। इसका एक बड़ा कारण यही है कि दोनों पक्षों से एक-एक सदस्य ही नए सिरे से मध्यस्थता के लिए आगे आए हैं।

यह स्वागतयोग्य है कि सभी पक्षकार और उनके वकील सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई 18 अक्टूबर की समय सीमा का पालन करने यानी इस तिथि तक अपनी दलीलें पूरी करने के प्रति सहमति व्यक्त कर रहे हैं। इस सहमति के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर के पहले फैसला देना सुनिश्चित करे। इसके लिए आवश्यक हो तो अवकाश के दिनों में कुछ कटौती की जा सकती है। आखिर जब प्रतिदिन सुनवाई की जा सकती है तो फिर अवकाश में कटौती भी की जा सकती है। चूंकि अयोध्या मामले में फैसले की घड़ी करीब आती दिखने लगी है इसलिए सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि वह टले नहीं। अपेक्षित समय सीमा में फैसला देना केवल इसलिए सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि सदियों पुराने इस विवाद के समाधान की प्रतीक्षा बहुत बेसब्री से की जा रही है, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अच्छा-खासा समय और संसाधन खपाया है। यह जाया हो, इसका कोई मतलब नहीं।

असंगठित क्षेत्र को संरक्षण

झारखंड में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संबल-संरक्षण प्रदान करने के इरादे से झारखंड में शुरू किए गए श्रमशक्ति अभियान का स्वागत किया जाना चाहिए। इसे सफल बनाने के लिए हर स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। यह सही है कि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में असंगठित क्षेत्र के मजदूर दिन-रात लगे रहते हैं। कई स्थानों पर तो इनके बूते ही कार्य का संपादन संभव हो पाता है। अफसोस की बात है कि ऐसे श्रमिकों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए, क्योंकि इनके हक को मजबूती से उठाने वालों की हर जगह कमी रहती है। इनके लिए लड़नेवाले आगे आने से परहेज करते हैं, जबकि संगठित क्षेत्र के मजदूरों की आवाज बनने की होड़ रहती है। इसलिए झारखंड से इनके कल्याण के लिए नई पहल दूसरों के लिए नजीर है। मुख्यमंत्री ने यह सही कहा है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है इसलिए सरकार खुद आगे आई है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सरकार इस काम को अंजाम देना चाहती है। इसकी शुरुआत सप्ताहव्यापी अभियान से की गई है। 25 सितंबर से दो अक्टूबर तक राज्य के सभी प्रखंडों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन किया जाना है ताकि पता चल सके कि राज्य में ऐसे श्रमिकों की संख्या कहां और कितनी है। किसी भी योजना को फलदायी बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि उसे शुरू करने से पहले यह पता हो कि उसके लाभुकों की संख्या कितनी होगी। उसी हिसाब से जरूरी संसाधनों का इंतजाम किया जाता है। अब राज्य के सभी जिम्मेदार तबके की यह जिम्मेदारी है कि इस अभियान को सफल बनाने में अपने स्तर से हरसंभव प्रयास करे। सबसे बड़ी बात यह कि इन श्रमिकों तक सरकार की नीति एवं नीयत की जानकारी सही तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकारी मशीनरी के साथ गांव की सरकार समेत दूसरे जन प्रतिनिधियों की इसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सियासी दलों एवं स्वयंसेवी संगठनों के अलावा कंपनियों एवं दूसरे तमाम प्रतिष्ठानों के संचालकों को भी इस अभियान को सफल बनाने में आगे आना होगा। तभी इस नेक सोच के अपेक्षित फलाफल की आस की जा सकेगी।

> दो अक्टूबर तक झारखंड में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन होना है ताकि पता चले कि राज्य में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है

अमेरिका से दोस्ती के साथ मतभेद भी

सी. उदयभास्कर

> हाउडी मोदी में भले ही जश्न का माहौल रहा हो, लेकिन मोदी-ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता में बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते पर सहमति न बन पाना चिंताजनक है

संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक और इससे इतर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का पहला पड़ाव बना 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम। मोदी के दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में 22 सितंबर को आयोजित इसी कार्यक्रम की रही। अमेरिकी मानकों के लिहाज से यह भारी-भरकम भीड़ वाला जलसा था जिसमें करीब 50,000 लोग शामिल हुए जिनमें ज्यादातर भारतवंशी ही थे। भले ही अधिकांश अमेरिकी नागरिक थे, लेकिन उन्हें विदेशों में बसे मोदी समर्थक भी कहा जा सकता है जो भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जुटे थे। अप्रत्याशित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें मौजूद रहे। कई रिपब्लिकन एवं डेमोक्रेट सांसदों ने भी इसमें शिरकत की। दोनों दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से कार्यक्रम का स्वरूप व्यापक हो गया।

ह्यूस्टन में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। चाहे वह व्यापार का मसला हो, सुरक्षा या राजनीतिक रुझान का, एकबारगी यही लगा कि विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेता मानों एक सुर में बोल रहे हों। इससे यही संकेत मिले कि सभी विवादित द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी और उनका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। इससे पहले भारत में ट्रंप को लेकर कुछ असहजता का भाव था। इसमें एक तो उनके उस बयान की भूमिका थी जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कथित रूप से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने के लिए कहा था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर नई दिल्ली को यह आशंका सता रही थी कि कहीं इस मसले पर पाकिस्तान को वाशिंगटन का साथ न मिल जाए। मोदी-ट्रंप मुलाकात से ये आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं। ट्रंप ने जहां भारतीय प्रधानमंत्री को खास दोस्त और महान नेता बताया वहीं मोदी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' का नारा भी उछाला। इससे बचा जाना चाहिए था, लेकिन मोदी की यही सियासी शैली है। ह्यूस्टन की गुलाबी तस्वीर कुछ समय के लिए ही टिक पाई। इसके चंद दिन बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उसके अगले रोज प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता में हकीकत से सामना हुआ। मोदी-ट्रंप वार्ता में भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय रिश्तों की स्थाई प्रकृति और अवरोध भी स्पष्ट हुए।

यह धारणा सही नहीं कि भारत और अमेरिका लंबे समय से साझा हितों को पोषित करते आए हैं। दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हालिया दौर की बात है। तकरीबन 34 वर्षों तक दोनों देश सुरक्षा एवं सामरिक हितों जैसे तमाम मुद्दों पर एक-दूसरे से काफी इतर रहे। रिश्तों में यह बर्फ एक दशक पहले ही पिघलनी शुरू हुई। इस दिशा में सक्रियता का आगाज 2008 के अंत में बुश-मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ। ह्यूस्टन में भले ही जश्न का माहौल रहा हो, लेकिन 24 सितंबर को जब दोनों नेता द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत के लिए बैठे तो उसमें बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते पर सहमति नहीं बन पाई। भारत को अमेरिका से अच्छा-खासा व्यापार लाभ मिलता है। इसमें भारत को लगभग 24 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष हासिल है। ऐसे में भारत ट्रंप की उन देशों की सूची में शामिल है जो अनुचित व्यापार नीतियां चला रहे हैं। ट्रंप ने इसे सुधारने का वादा किया है। इसके चलते अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को मिला जीएसपी दर्जा जून में वापस ले लिया। उम्मीद थी कि मोदी-ट्रंप द्विपक्षीय वार्ता में इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। यह अनुमान भी लगाया गया कि भारत भी अमेरिका से अधिक हाइड्रोकार्बन आयात की घोषणा करेगा, पर कोई द्विपक्षीय व्यापारिक करार नहीं हो सका। यह वैश्विक व्यापार परिदृश्य की जटिलताओं को दर्शाता है जो ट्रंप की औचक नीतियों और चीन के साथ व्यापार युद्ध के चलते लगातार अनिश्चित एवं अस्थिर बनता जा रहा है।

अवधेश राजपूत

व्यापार अधिशेष वाले देश के साथ परस्पर स्वीकार्य करार पर सहमति न बना पाने की नई दिल्ली की नाकामी वैश्विक परिदृश्य में कोई अच्छा संकेत नहीं है। फिलहाल भारत अमेरिका के साथ नहीं, बल्कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी आरसीईपी देशों के साथ समझौते पर काम कर रहा है जिनमें चीन और अधिकांश पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। इन ज्यादातर देशों के साथ भारत को भारी व्यापार घाटा हो रहा है। भारत की बेचैनी इससे और गहरी हो जाती है कि घरेलू विनिर्माताओं की कीमत पर चीनी वस्तुओं का बोलबाला बढ़ सकता है। प्रमुख व्यापारिक देशों या समूहों के साथ किसी स्वीकार्य व्यापार समझौते को मूर्त रूप देने में नई दिल्ली की नाकामी की जड़ें वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की कमजोरियों में छिपी हैं। भारत को अभी भी प्रतिस्पर्धी एवं गुणवत्तापरक विनिर्माता का दर्जा हासिल करना शेष है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा हो।

व्यापार को किनारे कर दें तो सुरक्षा और आतंकवाद के मसले पर भी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मोदी और ट्रंप के बीच असहमति नजर आई। ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जोर जहां वैश्विक आतंकवाद खासतौर से पाकिस्तान में फैली जिहाद की विषबेल पर था, लेकिन ट्रंप के लिए प्राथमिकताएं अलग थीं। इमरान खान के साथ संवाददाता सम्मेलन में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह पीएम मोदी के आकलन से सहमत हैं कि पाक आतंकवाद की धुरी बना हुआ है? ट्रंप ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा, 'मेरा इशारा ईरान की ओर अधिक है। वह देश सच में आतंकी है।'

पाकिस्तानी आतंकवाद और ईरान के बारे में धारणा को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन में यह मतभेद दशकों पुराना है और ह्यूस्टन में बने माहौल के बावजूद इसमें बदलाव के कोई आसार नहीं हैं। व्यापार और आतंकवाद के मसले पर ऐसे रुख का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग की जरा भी गुंजाइश नहीं। अमेरिका भारत के सैन्य साजोसामान के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है और दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सक्रियता भी समय के साथ बढ़ी है। प्रशांत महासागर में इन दिनों भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय मालाबार नौसैन्य अभ्यास जारी है। इस अभ्यास पर चीन की निगाह लगी होगी। यह भारत के लिए बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है। यह चुनौती पाकिस्तान नहीं, बल्कि चीन है। भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है, यह मसला दीर्घावधि में भारत की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए अहम बना रहेगा। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना अमेरिका और चीन, दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते कायम करे। इस लिहाज से अक्टूबर की शुरुआत में मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच तमिलनाडु में प्रस्तावित अनौपचारिक वार्ता खासी अहम होगी। यह नई दिल्ली को राह दिखाएगी कि वह बीजिंग और वाशिंगटन के साथ रिश्तों को कैसे साध सकती है।

(लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

प्लास्टिक के खिलाफ जरूरी पहल

डॉ. सूर्यकांत

> प्लास्टिक की उन तमाम वस्तुओं के विकल्प तलाशने जरूरी हैं जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सिंगल यूज यानी एक बार प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का आह्वान किए जाने के बाद से देश में उसके खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ है। आगामी दो अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की तैयारी की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार आज भारत में औसत व्यक्ति प्रतिवर्ष 11 किलो प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है, जबकि विश्व में यह 28 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। इसके बावजूद प्लास्टिक का उपयोग इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि हमारे यहां उसके निस्तारण की सही व्यवस्था नहीं बन सकी है। एक प्लास्टिक बैग अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। इसके कारण बहुत से लोग जब कुछ खरीदने जाते हैं तो कपड़े या जूट का थैला नहीं लेकर जाते। सामान बेचने वाले विक्रेता उन्हें पॉलीथिन के थैले में सामान दे देते हैं। इसके कारण ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है। इससे ऐसे जहरीले पदार्थ निकलते हैं जो मानव स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं।

प्लास्टिक आज जल प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहा है, इसकी वजह इस पर बढ़ती हमारी निर्भरता है। जैसे पानी पीने की बोतल, प्लास्टिक के चम्मच, टूथब्रश, थाली, कप, गिलास, बैग आदि। एक समय इनमें से अनेक वस्तुएं प्लास्टिक की नहीं होती थीं। दरअसल सहूलियत के कारण प्लास्टिक का अधिक उपयोग बढ़ा है। आज तमाम वस्तुओं की पैकिंग के लिए भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यहां तक कि बच्चों के खेलने के लिए भी प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाने लगे हैं। प्लास्टिक की ज्यादातर वस्तुएं एक बार में काम में लेने के बाद फेंक दी जाती हैं। ये इधर-उधर जमा होती रहती हैं और जब बारिश होती है तो ये पानी के साथ बहकर नदियों और नालों में चली जाती हैं। उसके बाद समुद्र में चली जाती हैं। कई बार तो इन प्लास्टिक की थैलियों के कारण नदी-नालों का बहाव रुक जाता है। प्लास्टिक की वस्तुएं हजारों वर्षों तक समुद्र में पड़ी रहती हैं। इनसे धीरे-धीरे जहरीले पदार्थ निकलते हैं, जो जल को प्रदूषित करते रहते हैं। कई बार समुद्री जीव प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं। इसके कारण उनके फेफड़ों या फिर श्वास नली में यह प्लास्टिक फंस जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यूनेस्को के अनुसार दुनिया में प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से लगभग 10 करोड़ समुद्री जीव-जंतु प्रति वर्ष मर रहे हैं। प्लास्टिक की विघटन प्रक्रिया में 400 से ज्यादा साल लग जाते हैं। इस दौरान वे जहरीली गैसें छोड़ते रहते हैं, जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। प्लास्टिक के कचरे को सही तरह निस्तारित करने के बजाय कई लोग उसे जला देते हैं। लोग समझते हैं कि जलाने से उसे नष्ट किया जा सकता है और प्रदूषण से भी बचा जा सकता है, लेकिन होता बिल्कुल उलट है। जब प्लास्टिक बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे घातक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब उसे जलाया जाता है तो ये सारे रसायन हवा में फैल जाते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्लास्टिक को जलाए जाने के कारण जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें ज्यादा देर तक सांस ली जाए तो कई बीमारियां हो सकती हैं। चूंकि प्लास्टिक का उपयोग दैनिक जीवन में खूब होने लगा है इसलिए लोगों पर उसका दुष्प्रभाव भी बढ़ रहा है। कहा जाता है कि मानव अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा प्लास्टिक से ही घिरा रहता है और उसी का सबसे ज्यादा उपयोग करता है। लोगों को दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन सभी में प्लास्टिक जहर घोल देता है। इसके चलते अनेक भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं।

मानव के अतिरिक्त पशु, पक्षी एवं वातावरण को भी इससे भयानक नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इससे बनी वस्तुओं का बहिष्कार आवश्यक है। दुनिया के अनेक देशों में ऐसा पहले से ही हो रहा है। बतौर उदाहरण कई लोग प्लास्टिक से बने टूथब्रश का इस्तेमाल छोड़ रहे हैं और पीने के पानी के लिए प्लास्टिक के बजाय स्टील की बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक के बैग और बोतल तब तक प्रयोग कर रहे हैं जब तक वे खराब नहीं हो जाते। इसी तरह प्लास्टिक से बनी हुई ऐसी वस्तुओं के इस्तेमाल से बच रहे हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है।

यह अच्छी बात है कि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव का प्रचार-प्रसार शुरू हो गया है, लेकिन आवश्यकता इसकी है कि प्लास्टिक की उन वस्तुओं के विकल्प तलाशे जाएं जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। कुछ वस्तुओं के विकल्प तो उपलब्ध हैं या फिर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की सभी वस्तुओं का विकल्प खोजने में समय लग सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आम लोगों को यथासंभव प्लास्टिक की वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। प्लास्टिक के नुकसान से छात्रों को भी परिचित कराया जाना चाहिए ताकि वे बचपन से ही प्लास्टिक दुष्प्रभाव के बारे में जानें। प्लास्टिक के उचित निस्तारण के तरीके भी खोजे जाने चाहिए। इस सिलसिले में प्रो. राजगोपालन वासुदेवन ने प्लास्टिक की समस्या का बहुत ही लाजवाब हल निकाला है। उन्होंने प्लास्टिक के जरिये सड़क बनाने की तकनीक की खोज की है। उनके शोध से पता चला है कि एक मजबूत सड़क बनाने में यह बहुत मददगार है। इस कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। कई देशों ने इस तकनीक को अपनाना भी शुरू कर दिया है। इसमें ब्रिटेन एवं नीदरलैंड सबसे ऊपर हैं। इससे निजात पाने के लिए कुछ देशों ने प्लास्टिक बैग पर आंशिक तो कुछ देशों ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। कुछ देश ऐसे प्लास्टिक की खोज के प्रयासों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका क्षरण जल्द हो जाए और जो इस प्रक्रिया में जल, जमीन या हवा को नुकसान न पहुंचाए। जब तक ऐसा प्लास्टिक नहीं मिलता तब तक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर हम न केवल पर्यावरण की रक्षा करने में मददगार बनेंगे, बल्कि स्वस्थ समाज की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे।

(लेखक इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी एंड एप्लायड इम्यूनोलॉजी के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मोक्ष का मार्ग

मानव जीवन में दो मार्ग हैं-एक बंधन का मार्ग और दूसरा मोक्ष का मार्ग। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि मृत्यु के बाद जब शरीर रूपी बंधन से मुक्ति मिलती है, तब मोक्ष मिलता है, पर सच्चाई यह है कि मनुष्य जीवित रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महाभारत में श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं, 'कर्म करते हुए और उन कर्मों को मन से परम सत्ता को अर्पण करते हुए यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो वह इसी जीवन में मोक्ष पा लेता है।' कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेकों अनेक बंधनों को काटना पड़ता है, जिनमें लोभ, मोह और अहं प्रमुख हैं। चूंकि बंधन हमेशा दुष्प्रवृत्तियों के ही होते हैं, इसलिए उनसे छुटकारा पा लेना ही मोक्ष है। यदि यह दूरदर्शिता हमारे अंदर आ जाए तो मोक्ष का तत्व ज्ञान समझते हुए हम जीवन को सफलता की चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। हमें मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि हर व्यक्ति इस परम पुरुषार्थ के लिए कर्म करे एवं परम तत्व की प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को सार्थक बनाए।

बंधन और मोक्ष में फर्क सिर्फ इतना-सा है कि जब आसुरी संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम बंधन की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन जब दैवीय संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। बंधन का मकड़जाल हमें जकड़े रहता है, लेकिन इससे छुटकारा पाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मोक्ष जरूरी है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है, उसमें क्रोध, मोह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका निर्णय समाज के हित में होना चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन इसके लिए श्रीकृष्ण ने पांडवों के मन में द्वेष नहीं, बल्कि अखंड भारत के कल्याण की भावना जगाई और एक संस्कारी राजा का आदर्श रखते हुए ईश्वर के लिए कर्म करने की भावना जगाकर युद्ध करने को कहा। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को जीवन जीने की कला कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, सुनने और मनन की क्षमता को बढ़ाना चाहिए और निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए।

आचार्य अनिल वत्स

सोशल मीडिया पर नियंत्रण जरूरी

अंशुमाली रस्तोगी

> सोशल मीडिया की शुरुआत लोगों को नजदीक लाने के लिहाज से की गई थी, न कि किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया पर नकेल कसने को कहा है। अब वाकई समय आ गया है, जब केंद्र सरकार सोशल मीडिया के खिलाफ कोई सख्त निर्णय ले। माना कि सोशल मीडिया स्वतंत्र अभिव्यक्ति का एक बड़ा माध्यम है। यहां कोई भी अपनी बात खुलकर कह-लिख सकता है। दोस्त बना सकता है, लेकिन यहां ट्रोल करने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने का हक किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता भी यही है।

ट्रोलिंग सोशल मीडिया का सबसे घृणित पक्ष है। आप सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध असहमति जता दीजिए, फिर देखिए आपको यहां कैसे और किस हद तक ट्रोल किया जाता है। ट्रोलिंग में अभद्र भाषा का जिस तरह प्रयोग किया जाता है, उसे किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा-माना जा सकता। अभी हाल ही में मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को, केबीसी में एक सवाल का उत्तर सही न दे पाने के कारण, जिस तरह फेसबुक और ट्विटर पर ट्रोल किया गया, वह बहुत ही दुखद था। कोई जरूरी तो नहीं कि सबको हर विषय का ज्ञान हो ही। कभी-कभी बहुत ही साधारण से सवाल पर हम भी चूक जाते हैं। कभी-कभी तो सोशल मीडिया 'बंदर के हाथ में उस्तरा' जैसा आभास देता है। किसी की भी गर्दन पर वार करने को तैयार।

वैसे सोशल मीडिया (खासकर फेसबुक और ट्विटर) को आधार से जोड़ने का प्रस्ताव भी बुरा नहीं। इससे कुछ हद तक तो लगाम लगेगी ही। फेक एकाउंट्स और खबरों में भी थोड़ी कमी आएगी। वरना तो होता यह है कि कैसी भी उल्टी खबर को सही बनाकर वायरल कर दिया जाता है। यह कहना गलत न होगा कि सोशल मीडिया पर 80 फीसद खबरें फेक ही होती हैं। समाज में कितने ही फसाद फेक न्यूज के कारण भड़के हैं। पिछले दिनों भीड़ द्वारा हिंसा में जो बढ़ोतरी हुई उसमें फेक न्यूज का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ ही मिनट में किसी भी खबर का वायरल हो जाना, चिंता का सबब बनता जा रहा है। सही और गलत की पहचान होना जरूरी है। नहीं तो बेकसूर लोग बेवजह ही मारे जाते रहेंगे।

इस सबके बावजूद कुछ लोगों ने समझदारी और धैर्य से काम लेते हुए खुद को सोशल मीडिया से दूर भी किया है, निरंतर कर भी रहे हैं। धीरे-धीरे वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने लगे हैं। खाली समय किताबों के साथ गुजारने लगे हैं। आपसी रिश्तों-संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। न फेक न्यूज पर विश्वास करते हैं, न ही उसे शेयर करते हैं। यह सब जरूरी है। नहीं तो हम ट्रोलिंग, फेक न्यूज, अभद्र भाषा आदि के अंधे कुएं में ही यों ही डूबते चले जाएंगे। बेहतर तो यही रहेगा कि केंद्र सरकार जितना जल्दी हो सके सोशल मीडिया के खिलाफ सख्त कानून बनाए, ताकि बात-बात पर इसका दुरुपयोग करने वालों पर अच्छे से लगाम कसी जा सके। सोशल मीडिया की शुरुआत अपनों को नजदीक लाने, अनजान लोगों से मित्रता बढ़ने के लिहाज से की गई थी, न कि किसी को ट्रोल करने या किसी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए। इसके लिए हमें खुद को सुधारना ही होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मोदी सरकार पर बढ़ता भरोसा

'अपेक्षाएं पूरी करने की चुनौती' शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकासात्मक कार्यों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है और उसके प्रभावस्वरूप बदल रही आम जनता की मानसिकता तथा अपेक्षाओं का भी उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से वर्ष 2014 के बाद नए भारत के रूप में देश की छवि सामने आ रही है। सामान्य व्यक्ति भी इस कार्य में स्वयं को भागीदार पा रहा है। रसोई गैस, शौचालय, बैंक खाते, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला, सौभाग्य, किसान कल्याणकारी योजनाएं, नारी सशक्तीकरण एवं सम्मान आदि अनेक ऐसे पहलू हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। ये सारे वही मुद्दे हैं जो लगभग स्वतंत्रता के बाद से निरंतर बने हुए थे। यह सत्य है कि जो ठीक दिशा में काम करता है जनता की अपेक्षाएं उसी से ही रहती हैं। निश्चित रूप से आज सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, चिकित्सा क्षेत्र, कुपोषण, प्रदूषण, जल संरक्षण आदि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी चुनौतियों के रूप में सामने खड़े हैं। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद तथा आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का एक बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखा गया है। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र पर चलते हुए इन चुनौतियों से पार पाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि मोदी सरकार इन अपेक्षाओं पर भी खरी उतरेगी।

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली

पाक की तिलमिलाहट

दैनिक जागरण के 26 सितंबर के अंक में शंकर शरण का लेख, अपनी ही नजरों में गिरता पाकिस्तान, में सही लिखा है कि उन्होंने अपनी मूल धरती, उसकी गौरवशाली संस्कृति, इतिहास, धर्म, साहित्य और समाज से घृणा करने को ही अपना स्वभाव बना लिया। पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, महंगाई चरम पर है। जनता भूख से बेहाल है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर का बेसुरा राग अलाप कर अपनी जनता का पेट भरने की जुगत लगा रहे हैं। पाकिस्तान की भूखी जनता को रोटी चाहिए, परमाणु बम की धौंस दिखाने से जनता का पेट नहीं भरेगा। इसी मानसिकता के कारण पाकिस्तान भारत से चार युद्ध लड़ चुका है और चारों में उसे शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी थी, तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि पाकिस्तान ने ऐसी मूर्खता की तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। वर्ष 1971 के युद्ध में तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया था, लेकिन वह फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से पहले पाकिस्तान को अपनी आंतरिक परिस्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। पाकिस्तान के कुछ राज्यों में ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। असल में पूरे विश्व में भारत को मिल रहे सम्मान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। इमरान खान को यह समझ लेना चाहिए कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। जिस दिन इमरान खान यह बात समझ जाएंगे सारी समस्या हल हो जाएगी।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

चूहों की बढ़ती संख्या

एक अनुमान के मुताबिक देश में 240 करोड़ से ज्यादा चूहे हैं। ये हर साल 40 करोड़ों लोगों की भूख मिटाने लायक अनाज खा जाते हैं। चूहों की बढ़ती तादाद व अनाज का इतना खा जाना चिंताजनक है। हम सबको इस समस्या पर भी चिंता करनी होगी, क्योंकि देश के कई लोगों को पर्याप्त मात्रा में दो जून का भोजन नसीब नहीं होता है। दरअसल प्रकृति ने जीव जंतुओं में संतुलन बनाने के लिए कई ऐसे जीव जंतु पैदा किए जो अपना आहार बनाकर संतुलन कायम रखते हैं। चूहा, सांप व बिल्ली का पसंदीदा आहार है, लेकिन धरा से सांपों के कम होने से चूहों की फौज ब